



तमिलनाडु में टीवीके की अनूठी राजनीति : राहुल पर चुप्पी साधकर मोदी संग मेट्रो में सफर करते रहे सीएम विजय

चेन्नई,(ए)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी राजनीति को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जुड़े राजनीतिक विवादों से लगातार दूर रखा है। हाल ही में दिल्ली में राहुल गांधी की हिरासत को लेकर विपक्षी दलों के तीव्र विरोध के बावजूद, उनकी चुप्पी ने ध्यान आकर्षित किया। इस घटना के महज दो दिन बाद, मुख्यमंत्री विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो में सफर करने और मंदिर दर्शन करते नजर आए, जो उनकी संतुलित राजनीतिक रणनीति का स्पष्ट संकेत है।दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर मार्च के दौरान राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी होने के बावजूद, मुख्यमंत्री विजय ने इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा।

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को चेन्नई दौर पर थे। मुख्यमंत्री विजय ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका गर्मजोशी से स्वागत



किया। दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले, राहुल गांधी भी चेन्नई पहुंचे थे और मुख्यमंत्री विजय ने अपने आवास पर उनका स्वागत व दोपहर के भोजन का आयोजन किया था। 24 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी का चेन्नई पहुंचना और मुख्यमंत्री विजय द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत

करना, कई राजनीतिक कयासों को जन्म दे गया।मेट्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बाद, दोनों नेता आईआईटी मद्रास भी गए, जहां उनके साथ सीएम विजय भी मौजूद थे। इसके बाद वे जलकंडेश्वराम मंदिर में भी साथ दिखे। आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के साथ विजय का शामिल होना

सामान्य है, लेकिन मंदिर में उनकी मौजूदगी ने सियासी गलियारों में विशेष चर्चा छेड़ दी है। इसे प्रोटोकॉल से हटकर देखा जा रहा है, खासकर तब जब विजय विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ मंदिर जाने के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

राहुल गांधी के चेन्नई पहुंचने पर भी मुख्यमंत्री विजय का कार्यक्रम शुरू में स्पष्ट नहीं था। यह भी पता नहीं था कि राहुल गांधी का उनके साथ दोपहर का भोजन होगा या नहीं। कांग्रेस के हलकों में भी यह माना गया कि यदि मुख्यमंत्री विजय स्वयं आगे नहीं बढ़ते, तो उन पर दबाव डालना उचित नहीं होगा। अंततः, विजय ने राहुल गांधी को अपने घर पर आमंत्रित किया और उनके साथ दोपहर का भोजन किया। इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री विजय अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी या विवाद में पड़े अपना काम करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से बेहतर तालमेल बनाए रखना है, साथ ही अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए गठबंधन सहयोगियों के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना है। इसी कारण विजय ने न तो राहुल गांधी की अनदेखी की और न ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने से इनकार किया, बल्कि दोनों के साथ एक संतुलन बनाए रखा।

दिल्ली में प्रदर्शन: 1975 की इमरजेंसी की तुलना पर छिड़ी बहस

नई दिल्ली(ए)। दिल्ली में 10 अक्टूबर 2026 को हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरों ने 1975 की इमरजेंसी के दौर की यादें ताजा कर दी हैं। उस समय प्रेस सेंसरशिप से लेकर विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी तक कई बड़े कदम उठाए गए थे। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या मौजूदा स्थिति वाकई उस दौर से मिलती-जुलती है या दोनों में बुनियादी अंतर हैं। 25 जून 1975 को लागू हुई इमरजेंसी, जो 21 मार्च 1977 तक चली, एक ऐसा दौर था जब देश ने कड़े प्रतिबंधों का सामना किया।

इस दौरान अखबारों में प्रकाशित होने वाली खबरों पर कड़ी सेंसरशिप लगाई गई, जिससे सरकार की आलोचना करने वाली सामग्री का प्रकाशन रुक गया। विपक्षी नेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और कुछ पत्रकारों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। विरोध-प्रदर्शनों और अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगा दी गई थी। नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण पर भी पाबंदी लग गई थी, जिससे सरकारी कार्रवाई को अदालतों में



चुनौती देना बेहद मुश्किल हो गया था। हाल ही में, 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं। इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रतिबंधों पर चर्चा हुई। कुछ क्षेत्रों में यातायात और मेट्रो सेवाओं पर पाबंदियों के साथ-साथ मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद किए जाने की भी खबरें आई थीं। दोनों स्थितियों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। 1975 में पूरे देश में संवैधानिक

प्रावधानों के तहत इमरजेंसी लागू थी, जो राष्ट्रव्यापी थी। वहीं, सीजेपी प्रदर्शन के दौरान रिपोर्ट की गई पाबंदियां एक विशिष्ट विरोध प्रदर्शन और संबंधित कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़ी हुई थीं, न कि पूरे देश पर लागू होने वाली संवैधानिक इमरजेंसी। इसलिए, दोनों घटनाओं को एक जैसा मानना सही नहीं है। हालांकि, विपक्षी पार्टियों और कॉकरोच जनता पार्टी ने इन पाबंदियों को अघोषित इमरजेंसी करार दिया है, जिससे यह बहस और भी तेज हो गई है।

मंत्री आठवले बोले- प्रधान का इस्तीफा ले लिया, ज्ञानेश को छोड़ो



करना चाहिए, न कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर। केंद्रीय मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन न करने की सलाह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को दी है। उन्होंने सीजेपी से छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करने का आग्रह किया, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष पर अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया। एक बयान में आठवले ने कहा कि सीजेपी को ज्ञानेश कुमार के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि सीजेपी का गठन नीत परीक्षा में हुए पेपर लीक के विरोध में हुआ था और उनकी मांगें, जिनमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था, पूरी हो चुकी हैं।

आठवले ने जोर दिया कि सीजेपी को छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली और इससे संबंधित अन्य कारणों पर आंदोलन करना चाहिए, न कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर। केंद्रीय मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि जिन 13 करोड़ वोटों को काटा गया है, उनमें से 6 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनका स्थानांतरण हुआ है, यानी वे नौकरी या व्यवसाय के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ मतदाताओं के नाम दो जगहों पर थे, जिनमें से एक नाम हटाया गया, जबकि लगभग 3 करोड़ लोग लापता थे। आठवले ने जोर देकर कहा कि यह वोट चोरी नहीं है। राहुल गांधी के वोट चोरी संबंधी बयानों पर भी आठवले ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी पार्टी के सीटों की संख्या बढ़ाने पर उसे वोट चोरी कहेंगे। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को सत्ता मिली थी, तब क्या वे भी वोट चोरी करते थे? आठवले ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को बेबुनियाद बताते हुए विपक्ष पर जानबूझकर अराजकता को निमंत्रण देने और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। यह पहली बार नहीं है जब आठवले ने सीजेपी को चेताया हो। 3 अक्टूबर को भी उन्होंने सीजेपी के अभिजीत दीपके को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी बंद करने की चेतावनी दी थी।

प्रार्थनाओं के तहत इमरजेंसी लागू थी, जो राष्ट्रव्यापी थी। वहीं, सीजेपी प्रदर्शन के दौरान रिपोर्ट की गई पाबंदियां एक विशिष्ट विरोध प्रदर्शन और संबंधित कानून-व्यवस्था की स्थिति से जुड़ी हुई थीं, न कि पूरे देश पर लागू होने वाली संवैधानिक इमरजेंसी। इसलिए, दोनों घटनाओं को एक जैसा मानना सही नहीं है। हालांकि, विपक्षी पार्टियों और कॉकरोच जनता पार्टी ने इन पाबंदियों को अघोषित इमरजेंसी करार दिया है, जिससे यह बहस और भी तेज हो गई है।

भारत के परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र से 7.5 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद

2047 तक निजी क्षेत्र को 30 गीगावाट क्षमता का योगदान देना चाहिए रांची,(ए)। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने कहा कि भारत में निजी क्षेत्र से करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने और उसके 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में 30 गीगावाट का योगदान देने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश में फिलहाल करीब 9 गीगावाट की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता है और 2047 तक इसे उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की योजना है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव का भी दायित्व संभाल रहे मोहंती ने एक इंटरव्यू में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 'न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' (एनपीसीआईएल) फिलहाल 24 परमाणु संयंत्रों का संचालन करता है। हमारा मानना है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा कारोबार में प्रवेश करना चाहिए और इसी वजह से नया कानून बनाया गया।" उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब से पांच साल बाद निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां संयंत्रों का संचालन कर रही होंगी। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि 2047 तक निजी क्षेत्र को 30 गीगावाट क्षमता का योगदान देना चाहिए। एक मेगावाट बिजली उत्पादन की लागत करीब 25 करोड़ रुपए है।" उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 में 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया' (शांति) अभियान लागू होना एक बड़ा नीतिगत बदलाव है और इस कानून के जरिए संवेदनशील गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण बरकरार रखते हुए परमाणु क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी संस्थाओं की व्यापक भागीदारी का रास्ता खोला गया है।

मोहंती ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन सरकारी उपक्रम एनपीसीआईएल फिलहाल करीब नौ गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु संयंत्रों का संचालन करता है। इसके अलावा करीब 13 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 17 अन्य संयंत्रों पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। मोहंती ने कहा कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है और खर्च का एक बड़ा हिस्सा निर्माण के शुरुआती चरणों में ही करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं से बनने वाली बिजली की लागत निवेशकों और बिजली खरीदने वालों के लिए एक अहम पहलू होगी। उन्होंने कहा कि बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ-साथ भारत विशेष जरूरतों के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाश रहा है। खासकर उन उद्योगों के लिए, जहां बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है।

पूर्व आईएएस और उनके बेटे ने सीट को लेकर बुजुर्ग को मार डाला!

नई दिल्ली(ए)। दिल्ली मेट्रो में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ सीट को लेकर हुए विवाद में एक यात्री की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर घटित हुई है, जिसने सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 6 बजे पवन शर्मा नामक यात्री अपनी मां दुर्गा देवी (लगभग 65 साल) के साथ मेट्रो में सवार होकर यमुना विहार की ओर जा रहे थे। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर पूर्व आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह ट्रेन में चढ़े। मेट्रो में बुजुर्गों के लिए अर्धशक्ति सीटों पर बैठे पवन और उनकी मां को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सीट को लेकर हुई यह मामूली बहस जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। आरोपियों, संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह ने पवन शर्मा को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बहस के दौरान पवन को थप्पड़ों से मारा गया और फिर दोनों ने मिलकर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इस जानलेवा हमले के बाद पवन शर्मा कथित तौर पर बेहोश हो गए। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर, प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक आदमी के बेहोश पड़े होने की सूचना शाम करीब 6 बजे पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश पवन शर्मा को तत्काल एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने पवन शर्मा को मृत घोषित कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी संजय प्रताप सिंह नोएडा के रहने वाले हैं।

भाजपा के कश्यप ने की अखिलेश से मुलाकात, यूपी में गरमा गई सियासत

बरेली में मुख्यमंत्री के दौरे से पहले राजनीतिक भूचाल

बरेली(ए)। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली के दौर पर आ रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले जिले का राजनीतिक समीकरण बदल गया है। आंवला से लगातार दो बार सांसद रहे और पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे धर्मेन्द्र कश्यप ने भाजपा से इस्तीफा देकर रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर बड़ा सियासी दांव चला है।

धर्मेन्द्र कश्यप ने अपनी बेटी कीर्ति के साथ अखिलेश से मुलाकात की और उसके लिए बिथरी चैनपुर सीट पर दावा भी ठेक दिया। उनके इस कदम से समाजवादी पार्टी में भी हलचल मच गई है, क्योंकि सपा के वरिष्ठ नेता वीरपाल सिंह यादव अपने बेटे डॉ. देवेन्द्र यादव की अनदेखी की और न ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने से इनकार किया, बल्कि दोनों के साथ एक संतुलन बनाए रखा।



शिक्षक विधान परिषद सीट से भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत और सभा स्थल पर वाटरपूफ पंडाल की व्यवस्था शामिल है। धर्मेन्द्र कश्यप के पिछले कुछ दिनों में उठाए गए कदमों से जिले में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का रख किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात के बाद पार्टी में उनके शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। इसकी विधिवत घोषणा 27 अक्टूबर को लखनऊ में एक कार्यक्रम में की जाएगी, जहां वे अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे। धर्मेन्द्र कश्यप अपनी बेटी कीर्ति कश्यप को बिथरी चैनपुर सीट से चुनाव लड़ाने की इच्छा पहले

ही जता चुके हैं, और उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बरेली की सियासत में हलचल उस वक्त और तेज हो गई, जब सपा के वरिष्ठ नेता वीरपाल सिंह यादव को आंवला विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। माना जा रहा है कि वीरपाल अपने बेटे डॉ. देवेन्द्र यादव के लिए बिथरी चैनपुर सीट से टिकट की पैरवी कर रहे थे, लेकिन इसी सीट पर धर्मेन्द्र कश्यप अपनी बेटी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए ही सपा प्रमुख ने वीरपाल सिंह यादव और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को लखनऊ बुलाकर समीकरणों पर चर्चा की। चर्चा के बाद वीरपाल को आंवला की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसे उनकी राजनीतिक भूमिका के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग: सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेगा विपक्ष

नई दिल्ली,(ए)। विपक्षी दल सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करते हुए उच्चतम न्यायालय तक मार्च करेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरेगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था, ताकि उनके समक्ष कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा सके। हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने राहुल गांधी से यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया कि ऐसे मुद्दे पहले से ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

प्रधान न्यायाधीश के मुलाकात से इनकार के बावजूद विपक्षी नेता उच्चतम न्यायालय तक मार्च करेंगे। कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को चले दिल्ली-लोकतंत्र के लिए मार्च नाम दिया है। पार्टी के अनुसार, प्रदर्शनकारी दोपहर डेढ़ बजे कर्नाट प्लेस-बाराखंबा रोड चौहान पर एकत्र होंगे। इस मार्च में खरेगे, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तुषमूल नेता ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के



प्रतिनिधि तथा युवाओं के भाग लेने की संभावना है। राहुल गांधी ने रविवार को कहा था कि विपक्षी दल, नागरिक संगठन के प्रतिनिधि और युवा सोमवार को उच्चतम न्यायालय तक मार्च करेंगे और वोट चोरी पर रोक लगाने, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया रोकने की मांग करेंगे। उन्होंने शनिवार के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे युवाओं के साथ पुलिसकर्मियों और भाजपा समर्थकों ने मारपीट की।

शनिवार को प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए मेट्रो और ट्रेन सेवाओं पर पाबंदियां लगाई गई थीं तथा दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं। विपक्षी दल बीजेपी सरकार से प्रधानमंत्री और भाजपा पर वोट चोरी के जरिये चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तत्काल हटाया जाए।

ध्रुव राठी बोले- मेरा सीजेपी से कोई संबंध नहीं

नई दिल्ली(ए)। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से अपना कोई रिश्ता होने से इनकार किया है, जबकि वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उसके आंदोलन में शामिल हुए। विदेश में रहकर भारतीय राजनीति और सरकार की आलोचना के लिए जाने जाने वाले राठी ने कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर इस प्रदर्शन में शामिल होने आए थे, उनका सीजेपी से किसी तरह का जुड़ाव नहीं है। यूट्यूब पर करीब 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले ध्रुव राठी को सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके और सौरभ दास का दोस्त बताया जाता है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के पहले आंदोलन के दौरान भी वह अक्सर अभिजीत दीपके के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए दिखते थे। अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में उन्होंने खुद भी शामिल होने का फैसला किया। बंगलुरु में 8 अक्टूबर को आयोजित प्रदर्शन से ठीक पहले भारत आए ध्रुव राठी ने उस दिन मंच से भाषण भी दिया और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के जरिए वोट चोरी के आरोप लगाए। राठी 10 अक्टूबर को सीजेपी की ओर से दिल्ली में घोषित प्रदर्शन में भी हिस्सा लेना चाहते थे। वह इसके लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। शुक्रवार शाम वह इंडिया गेट गए और वहां से एक वीडियो बनाकर प्रदर्शन में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने की अपील की। 10 अक्टूबर को अभिजीत दीपके को सुबह ही उनके गुरुग्राम स्थित घर से हिरासत में ले लिया गया। उसी दिन ध्रुव राठी को भी दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया। 20 से अधिक घंटे तक हिरासत में रहने के बाद छोड़े गए ध्रुव राठी ने बाद में आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें घसीटकर बेडरूम से ले गई और इस दौरान उन्हें चोटें भी आईं। ध्रुव राठी भले ही पहले धर्मेन्द्र प्रधान और अब ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर सीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सीजेपी से किसी तरह के जुड़ाव या रिस्ते से इनकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह सीजेपी में कोई पद नहीं रखते हैं।

